**घरेलू व विदेशी बाजारों में मांग घटने से सोने की चमक घटी**

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** विदेश के कमजोर रुझानों के बीच स्थानीय ज्वेलरों की ओर से मांग घटने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 100 रुपये गिरकर 32,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी घटने के कारण चांदी भी 145 रुपये गिरकर 38,425 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रक्रिया में बाधक बन रहे मुद्दों का दो-तीन साल में निराकरण हो जाने की उम्मीद है। उसके बाद इसे लागू करना और सरल हो जाएगा।

— एमएस साहू, चेयरपर्सन, आइबीबीआइ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेंसेक्स | 38,564.88 ▼ 80.30 | निफ्टी | 11,575.95 ▼ 18.50 | सोना प्रति दस ग्राम | ₹ 32,770 ▼ ₹100 | चांदी प्रति किलोग्राम | ₹ 38,425 ▼ ₹145 | $ डॉलर | ₹ 69.62 ▼ ₹ 0.05 | क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल | $ 74.28 |

**इंतजार ▶ कर्मचारियों, वेंडरों व विमानों के साथ होने के आधार पर सीईओ ने जताया भरोसा**

# सीईओ दुबे को अब भी जेट एयरवेज के फिर से उड़ान भरने की उम्मीद

**कहा, जेट के स्लॉट अस्थायी तौर पर ही दूसरी एयरलाइनों को दिए जा रहे**

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

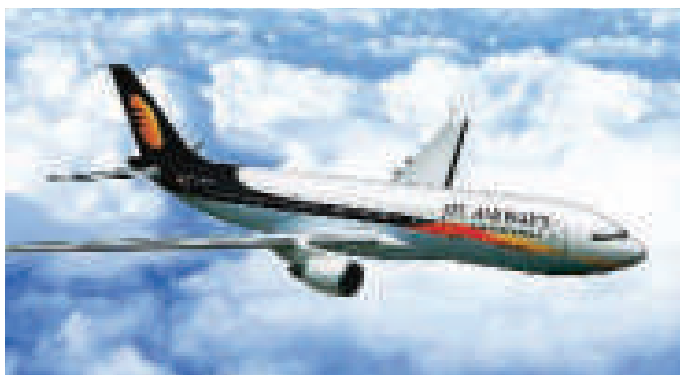

जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे को अब भी उम्मीद है कि एयरलाइन फिर से उड़ान भरने में कामयाब होगी। उनका कहना है कि हजारों कर्मचारी और वेंडर अब भी जेट एयरवेज के साथ खड़े हैं। साथ ही सरकार ने भी जेट के स्लॉट स्थायी रूप से दूसरी एयरलाइनों को नहीं देने का भरोसा दिया है। ऐसे में नए निवेशक की तलाश में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। दुबे की उम्मीदों को ब्रिटेन के एक स्टार्टअप निवेशक के जेट को खरीदने के प्रस्ताव से बल मिला है। जैसन अन्सवर्थ नामक ये निवेशक एटमास्फियर इंटरनेशनल एयरलाइंस का मालिक है। यह एयरलाइन दिसंबर तक उड़ानें शुरू करना चाहती है। अन्सवर्थ ने दुबे को पत्र लिखकर जेट एयरवेज में मालिकाना हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। अन्सवर्थ ने कहा कि दुबे ने उससे जेट एयरवेज के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क में रहने को कहा है।

बैंकों के मदद से इनकार के बाद जेट एयरवेज ने 17 अप्रैल से अपनी उड़ाने पूरी तरह से बंद कर दी थीं। जिसके बाद सड़क पर आ गए इसके हजारों कर्मचारियों ने सरकार से दखल की गुहार लगाई थी। इस सिलसिले में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने उनसे निवेशक तलाशने के लिए चल रही निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने को कहा था। जेट के कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी गुहार लगा चुके हैं। कभी 23 हजार कर्मचारियों वाली जेट एयरवेज के पास अब केवल 1527 पायलटों समेत करीब 17 हजार कर्मचारी बचे हैं। पिछले सात महीनों में इसके लगभग पांच हजार कर्मचारी दूसरी एयरलाइनों में जा चुके हैं। इनमें 410 पायलट शामिल हैं।

अधिकांश कर्मचारी हालांकि अब भी बेहतरी की उम्मीद में जेट के साथ बने हुए हैं। दुबे को इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे जेट के दुबारा खड़े होने का भरोसा है। यही नहीं, दूसरी एयरलाइनों द्वारा जेट के विमान उड़ाने को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही वे विमान अब दूसरी एयरलाइनों के हाथ में हैं, लेकिन इनका स्वामित्व अब भी जेट के ही पास है और जब स्थितियां अनुकूल होंगी तब जेट उन्हें पुनः हासिल कर लेगी।

**स्पाइसजेट का नई उड़ानों का ऐलान :** इस बीच जेट के कई बोइंग-737 श्रेणी के विमान वेट लीज पर लेने वाली स्पाइसजेट ने 26 अप्रैल से दिल्ली और मुंबई से 28 नई दैनिक उड़ानें प्रारंभ करने का एलान किया है। इन उड़ानों के लिए सरकार की ओर से उसे जेट के कई स्लॉट भी अस्थायी तौर पर मिल गए हैं। मंगलवार को स्पाइसजेट ने कहा कि ये उड़ाने मुंबई जयपुर, अमृतसर, मंगलुरु, कोयंबटूर के लिए होंगी। यही नहीं, स्पाइसजेट मुंबई-पटना, मुंबई-हैदराबाद तथा मुंबई-कोलकाता तथा दिल्ली-पटना और दिल्ली-बंगलुरु मार्गों पर अपनी उड़ानों के फेरे भी बढ़ाने जा रही है।

घरेलू उड़ानों के अलावा स्पाइसजेट ने मई के अंत तक मुंबई से काठमांडू, ढाका, कोलंबो, हांगकांग, बैंकाक, जेद्दा, दुबई और रियाद के बीच नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने का फैसला भी किया है।

# ईरान पर लगे प्रतिबंध से गड़बड़ा सकता है भारत के तेल आयात का गणित

**जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली**

ईरान से तेल नहीं खरीद पाने का असर भारत पर कई तरीके से पड़ेगा। एक तो भारत अपने एक विश्वसनीय तेल आपूर्तिकर्ता देश से हाथ धो बैठेगा, वहीं महंगा क्रूड खरीदने से देश के तेल आयात बिल में भी भारी इजाफा हो सकता है। पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में भारत का तेल आयात बिल तकरीबन 125 अरब डॉलर का था जो वर्ष 2017-18 के मुकाबले 42 फीसद ज्यादा था। अगर क्रूड इस वर्ष महंगा हुआ तो तेल आयात बिल और बढ़ जाएगा। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वर्ष 2017-18 में भारत ने ईरान से 2.26 करोड़ टन तेल खरीदा था जो वर्ष 2018-19 में बढ़ कर 2.4 करोड़ टन हो गया था। इस दौरान देश का कुल तेल आयात 22 करोड़ टन से बढ़ कर 22.86 करोड़ टन हो गया था। चालू वर्ष में इसके बढ़ने के पूरे आसार हैं। क्योंकि एक तो भारत के कुल तेल खपत में घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी घटती जा रही है। छह वर्ष पहले भारत अपनी जरूरत का 74 फीसद तेल बाहर से आयात करता था, जबकि वर्ष 2017-18 में 83 फीसद आयात किया गया था। चालू वित्त वर्ष में घरेलू उत्पादन में कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं है, जबकि आर्थिक विकास दर 7 फीसद से ज्यादा रहने की वजह से मांग में भी इजाफा होने के आसार हैं।

ईरान से आयातित तेल की कमी भारत को इसलिए भी महसूस होगी कि वह हमेशा जरूरत के वक्त भारत को आसान शर्तों पर तेल की आपूर्ति करता रहा है। ईरान के तेल बाजार से हट जाने की वजह से क्रूड की कीमत में तेजी आने लगी है, इसका भी खामियाजा भारत को उठाना पड़ेगा। ईरान पर पूरा प्रतिबंध लागू होने से पहले वेनेजुएला और लीबिया जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों से भी आपूर्ति प्रभावित हो गई है। साथ ही तेल उत्पादक देशों के संगठन (ओपेक) ने मार्च, 2019 में ही कुल तेल उत्पादन में 15 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करने का फैसला किया है। इससे कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की संभावना जताई जा रही है। सोमवार को कच्चे तेल की कीमत छह महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।

बहरहाल, भारत ने दूसरे वैकल्पिक बाजारों से बात शुरू कर दी है। सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ईराक, मैक्सिको और अमेरिका से ज्यादा क्रूड खरीदा जा सकता है लेकिन इन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। गौरतलब है कि महंगा क्रूड खरीदने से तेल आयात बिल बढ़ता है जिसका असर चालू खाते में घाटे (आयात व निर्यात पर खर्च राशि का अंतर) के रूप में दिखाई देता है। चालू खाते में घाटा बढ़ने का असर देश में महंगाई पर भी पड़ता है और डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होता है। सोमवार को ही डॉलर के मुकाबले रुपये में 32 पैसे की गिरावट के लिए क्रूड के महंगा होने की संभावना को ही जिम्मेदार ठहराया गया था।

# आइईपीएफ ने वसूले 1,514 करोड़ रुपये

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

- **15 साल से एक कंपनी के पास पड़ी थी निवेशकों की यह राशि**
- **निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने में होगा इस रकम का इस्तेमाल**

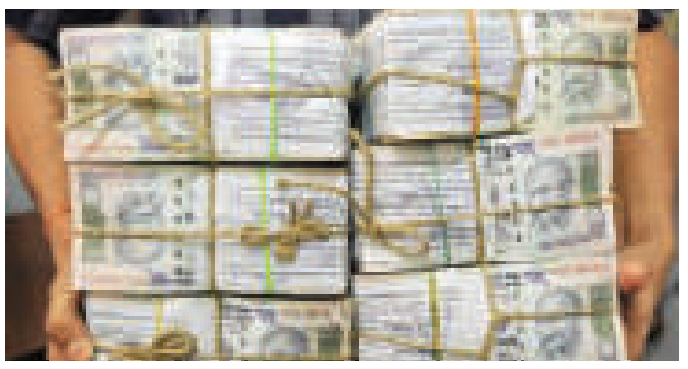

सरकारी अथॉरिटी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आइईपीएफ) ने निजी क्षेत्र की कंपनी पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास पड़ी हुई निवेशकों की 1,514 करोड़ रुपये की राशि को वसूल कर लिया है। कंपनी के पास यह धनराशि 15 साल से जमा थी और इस पर किसी भी निवेशक ने दावा नहीं किया था। जिन निवेशकों की यह धनराशि थी, उनमें सर्वाधिक निवेशक पश्चिम बंगाल के थे।

आइईपीएफ का गठन कंपनी कानून 2013 के तहत किया गया है। यह अथॉरिटी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि आइईपीएफ ने पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से निवेशकों की 1,514 करोड़ रुपये जमाराशि को वसूलने में सफलता हासिल की है। निवेशकों की यह राशि कंपनी के पास पिछले 15 साल से जमा थी और इस पर निवेशकों ने दावा नहीं किया था। कंपनी ने 1.49 करोड़ डिपॉजिट सर्टिफिकेट जारी कर यह राशि जुटाई थी। खास बात यह है कि लगभग आधी राशि दो हजार रुपये या इससे कम मूल्य के डिपॉजिट सर्टिफिकेट जारी करके जुटाई गई थी। वैसे तो कंपनी में यह राशि जमा कराने वाले निवेशक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निवेशक पश्चिम बंगाल में हैं। इसके अलावा कंपनी ने जो डिविडेंड जारी किया और जिस पर किसी ने दावा नहीं किया था, उसे भी आइईपीएफ के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। आइईपीएफ के पास 4,138 करोड़ रुपये का कोष है। कंपनियों ने 21,232 करोड़ रुपये मूल्य के 65 करोड़ शेयर भी आइईपीएफ को ट्रांसफर किये हैं।

आइईपीएफ एक ऑनलाइन सुविधा भी शुरू करेगी, जिसके जरिये छोटे-निवेशकों से भी आसानी से यह सूचना मंगाई जा सकेगी कि उनकी कौन-कौन सी जमा राशियां परिपक्व हो गयी हैं और उनका भुगतान भी बाकी है। इसके अलावा आइईपीएफ ने अन्य कंपनियों को भी 4,000 से अधिक नोटिस जारी कर उन जमा राशियों का ब्यौरा देने को कहा है, जिनके भुगतान के लिए किसी निवेशक ने दावा नहीं किया है।

# 250 करोड़ की मुनाफाखोरी में फंसी पीएंडजी इंडिया

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** एफएमसीजी कंपनी पीएंडजी इंडिया करीब 250 करोड़ रुपये की मुनाफाखोरी में फंस गई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मुनाफाखोरी जांच एजेंसी ने कंपनी को जीएसटी दरों में हुई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाने का दोषी पाया है। जीएसटी की स्थायी समिति को कंपनी की मुनाफाखोरी के बारे में शिकायत मिली थी। इसके आधार पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटीयरिंग (डीजीएपी) ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की थी। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 15 नवंबर 2017 से पहले और बाद की कीमतों की जांच की गई। डीजीएपी ने जांच में पाया कि कंपनी ने कई उत्पादों की कीमतों में कमी नहीं की है, जबकि उन उत्पादों की जीएसटी दरों को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर दिया गया था।

एक अधिकारी ने कहा कि डीजीएपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएंडजी इंडिया ने 250 करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी की है। अब इस मामले में कंपनी का पक्ष सुनने के बाद नेशनल एंटी प्रोफिटीयरिंग अथॉरिटी अंतिम तौर पर यह बताएगी कि कंपनी ने कितने की मुनाफाखोरी की है।

- **एफएमसीजी कंपनी ने ग्राहकों को नहीं दिया जीएसटी में हुई कटौती का लाभ**
- **जीएसटी की मुनाफाखोरी जांच एजेंसी ने कंपनी को पाया दोषी**
- **नेशनल एंटी प्रोफिटीयरिंग अथॉरिटी कंपनी का पक्ष सुनने के बाद देगा अंतिम फैसला**

जीएसटी काउंसिल ने 15 नवंबर 2017 के प्रभाव से 178 उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटा दी थीं। वॉशिंग पाउडर, शैंपू, कॉस्मेटिक्स और डेंटल ह्वाइजीन उत्पादों पर जीएसटी की दर को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर दिया गया था। जीएसटी के एंटी प्रोफिटेयरिंग नियमों के अनुसार कंपनियों को जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। इसके लिए उत्पादों की कीमतों में भी उतनी कटौती करनी होती है, जितनी कटौती टैक्स रेट में हुई है। लेकिन ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि कंपनियों ने उत्पादों के बेस प्राइस को बढ़ा दिया और उसपर कम जीएसटी दर लगाकर उतनी ही एमआरपी तय कर दी, जितनी जीएसटी कटौती से पहले थी।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक जिम्मेदार कंपनी होने का नाते पीएंडजी हमेशा अपने ग्राहकों को जीएसटी दरों में होने वाली कटौती का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा कि वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करेगी और इस बारे में स्पष्टीकरण पेश करेगी। उम्मीद है कि प्राधिकरण जीएसटी दरों में हुई कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने की उसकी प्रक्रिया की सराहना करेगा।

कंपनी के प्रमुख ब्रांडों में वाशिंग पाउडर एरियल और टाइड, शैंपू ब्रांड हेड्स एंड शोल्डर्स और पैंटीन, कॉस्मैटिक्स ब्रांड ओले और शेविंग व डेंटल हाइजीन ब्रांड जिलेट और ओरल-बी शामिल हैं। कंपनी पैंपर्स, विक्स और सैनिटरी नैपकिन व्हिस्पर का भी उत्पादन करती है।

# क्रूड के आयात की चिंता पर बाजार में गिरावट जारी

**मुंबई, प्रेट्र :** ईरान के तेल आयातकों को और छूट नहीं देने के अमेरिका के फैसले से कच्चा तेल महंगा होने और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका से मंगलवार को लगातार तीसरे दिन देश के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 80.30 अंकों की गिरावट के साथ 38,564.88 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 18.50 अंकों की गिरावट के साथ 11,575.95 पर बंद हुआ।

तिमाही नतीजों और लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे मतदान को देखते हुए भी निवेशकों ने बाजार में बढ़-चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। सेंसेक्स में मारुति सुजुकी में सर्वाधिक 3.60 फीसद गिरावट रही। यस बैंक, इंडसइंड बैंक और टाटा स्टील में भी दो फीसद से अधिक गिरावट रही। दूसरी ओर ओएनजीसी में सर्वाधिक 3.93 फीसद तेजी रही। सन फार्मा में 3.08 फीसद तेजी रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी रही।

- **बीएसई का सेंसेक्स 80.30 अंकों की गिरावट के साथ 38,564.88 पर बंद हुआ**
- **एनएसई का निफ्टी 18.50 अंक फिसलकर 11,575.95 पर हुआ स्थिर**

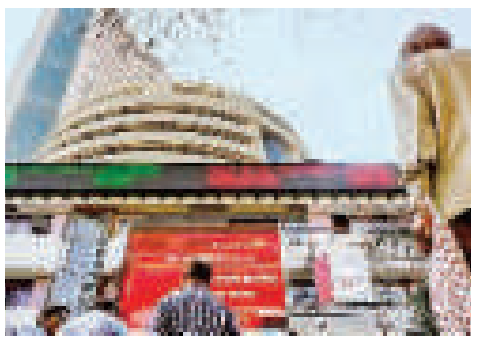

सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के टेलीकॉम सेक्टर में सर्वाधिक 1.38 फीसद गिरावट रही। दूसरी ओर ऊर्जा सेक्टर में 1.25 फीसद की सर्वाधिक तेजी रही। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि कच्चे तेज में तेजी के रुझान को देखते हुए निवेशक बाजार से दूरी बनाए रख सकते हैं। चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने तक बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान तिमाही नतीजे निवेशकों को अच्छे शेयर लपकने में मदद करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि वे ईरान के तेल आयातकों को प्रतिबंध से और अधिक छूट नहीं देंगे। इस फैसले से निवेश के माहौल पर नकारात्मक असर पड़ा है। ट्रंप के फैसले से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी, जिससे क्रूड महंगा होगा। इसका भारत सहित अन्य तेल आयातक देशों पर बुरा असर होगा, क्योंकि इससे वित्तीय घाटा बढ़ेगा और इसके साथ ही मुद्रा भी कमजोर होगी।

शेयरखान के एडवायजरी प्रमुख हेमांग जानी ने कहा कि तिमाही नतीजों के दौर से आने वाले दिनों में बाजार का रुझान तय होगा। निवेशकों की नजर चुनाव संबंधी घटनाक्रमों पर भी टिकी हुई है। केंद्र में मजबूत सरकार निवेश के माहौल के लिए सकारात्मक होती है। चुनाव के बाद बाजार में तेजी आने की उम्मीद है।

इस बीच बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने 237.47 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिक्री की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआइआइ) ने 198.35 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की थी।

# अब कोल पावर प्लांट नहीं लगाएगी टाटा

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** टाटा समूह की कंपनी टाटा पावर अब स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन पर अधिक ध्यान देगी और नए कोयला आधारित बिजली प्लांटों के निर्माण से अब धीरे-धीरे कदम पीछे खीचेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आइईईएफए) द्वारा मंगलवार को जारी 'टाटा पावर : रिन्यूएबल्स टु पावर ग्रोथ' रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने हाल में ही स्पष्ट किया है कि अब वह नए कोयला आधारित बिजली प्लांट बनाने में रुचि नहीं लेगी।

रिपोर्ट में लंबी अवधि के लिए कंपनी की योजना का उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक आने वाले समय में कंपनी के नए निर्माण में नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस बढ़ता जाएगा। आइईईएफए के एनर्जी फाइनेंस एनालिस्ट सिमॉन निकोलस ने एक बयान में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलावों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा पर टाटा पावर का नया फोकस वाजिब लगता है। कंपनी की 'रणनीतिक सोच 2025' के मुताबिक 2025 तक कंपनी के नए क्षमता विस्तार में 70 फीसद योगदान सौर, पवन ऊर्जा और पनबिजली का हो जाएगा।

- **कंपनी अब नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर अधिक ध्यान देगी**
- **2025 तक नई क्षमता में 70 फीसद योगदान सौर, पवन ऊर्जा और पनबिजली का हो जाएगा**

रिपोर्ट के मुताबिक टाटा पावर की ताप बिजली में अधिकतम योगदान मुंद्रा कोयला आधारित बिजली प्लांट का है, जो देश के सबसे बड़े पावर प्लांट्स में से एक है। इस प्लांट को लगातार घाटा हो रहा है। इससे कंपनी का कुल वित्तीय प्रदर्शन गड़बड़ा रहा है। निकोलस ने कहा कि मुंद्रा प्लांट से टाटा को मिले अनुभव के कारण कंपनी अब नया कोयला आधारित पावर प्लांट नहीं लगाना चाहती है। कोयला आधारित प्लांट से कंपनी की दूरी उम्मीद से अधिक तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर कंपनी का नवीरणीय परिचालन काफी लाभ में चल रहा है।

# चीन सीमा तक सड़क निर्माण की बड़ी बाधा दूर, पुल तैयार

**संवाद सूत्र, पिथौरागढ़**

चीन सीमा तक सड़क निर्माण की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। सीमा सड़क संगठन ने अतिसंवेदनशील नजंग में पुल तैयार कर लिया है। पांच किलोमीटर सड़क का निर्माण हो जाने के बाद कैलास मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव नाबीढांग भी सड़क से जुड़ जाएगा।

भौगोलिक रूप से बेहद दुरूह लखनपुर से नजंग तक का हिस्सा बेहद संवेदनशील है। बीते वर्ष यहां हुए भूस्खलन से कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया था। इसके चलते बीते वर्ष कैलास मानसरोवर यात्रा का संचालन पैदल नहीं हो सका था। यात्रियों को पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे गुंजी ले जाना पड़ा। मार्ग बंद हो जाने से व्यास घाटी के लोगों को माइग्रेशन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अपने मूल गांवों तक पहुंचने के लिए लोगों को वाया नेपाल होकर भारत में आना पड़ा। इसके लिए नेपाल सरकार की मदद से दो अस्थायी पुल बनाए गए थे। सीमा सड़क संगठन के सूत्रों के अनुसार कैलास मानसरोवर यात्रा पथ के इस हिस्से को ठीक कराने के लिए पिछले छह माह से जुटा हुआ था। संगठन ने मंगलवार को नजंग में मोटर पुल बनाने का काम पूरा कर लिया। नजंग से आगे दो किलोमीटर सड़क का निर्माण भी पूरा हो चुका है।

### मालपा और लमारी तक सड़क निर्माण का चल रहा कार्य

मालपा और लमारी तक सड़क बनाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। पांच किलोमीटर लंबे इस हिस्से का निर्माण पूरा होते ही गर्बाधार से कैलास मानसरोवर यात्रा के अंतिम पैदल पड़ाव नाबीढांग तक सड़क तैयार हो जाएगी। नजंग में पुल बन जाने से एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। बता दें गर्बाधार से भारत चीन के बीच सीमा पर बनाने वाले लिपूलेख दर्रे तक लगभग 70 किलोमीटर की लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य 2020 तय किया गया है।

# आयुष्मान में इलाज नहीं देने पर निजी अस्पताल पर 11.82 लाख जुर्माना

**जासं, देहरादून:** अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की लाभार्थी को उपचार न देने पर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण ने श्री महंत इंदिरेश अस्पताल पर 11,82,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह अस्पताल द्वारा मरीज को अनाधिकृत रूप से दिए गए एस्टिमेट की पांच गुना रकम है। जिसे अस्पताल को एक सप्ताह के भीतर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण में जमा करना होगा। बता दें, इस प्रकरण में मरीज की समय पर इलाज न मिलने के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

दरअसल, 18 जनवरी को कोटद्वार निवासी पिंकी प्रसाद को चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार में भर्ती कराया गया था। हृदय रोग के कारण उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने 21 जनवरी को उन्हें श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अमित ने उन्हें आइसीयू में रखा गया। बताया कि मरीज को ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है, 29 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और 2,36,500 रुपये का एस्टिमेट सौंप दिया गया।

# 'स्पेशल-26' की तर्ज पर संचालित आयकर विभाग पर पुलिस का छापा

**नईदुनिया, इंदौर**

मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जो आयकर अफसर बनकर वर्षों से ठगी कर रहे थे। गिरोह का सरगना समानांतर आयकर विभाग संचालित कर रहा था। वह स्वयं को चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताता था। साथियों को ही सीनियर फील्ड ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर बना लिया। इसके बाद युवाओं से 40 लाख रुपये ऐंठ लिए। उसकी गाड़ी पर भारत सरकार की नेम प्लेट और खाकी वर्दी पहने गनमैन साथ रखता था। उसने हिंदी फिल्म 'स्पेशल-26' की तर्ज पर कई जगह छापे मारकर रुपये वसूले हैं। ठग ने 30 कारोबारी, प्रॉपर्टी ब्रोकर, किसान, दुकानदारों के घर दबिश देने के लिए सर्वे तक करवा लिए थे। आरोपित के दफ्तर से रिकॉर्ड, सर्वे की फाइलें, रजिस्टर, लैपटॉप, प्रिंटर, कार (सफारी), नेमप्लेट, आयकर की सील, नियुक्ति पत्र, आइडी कार्ड मिले हैं।

एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र के मुताबिक सरगना देवेंद्र (29) ने फर्जी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर सिलीकॉन सिटी में एक फ्लैट में फर्जी आयकर कार्यालय खोल लिया था। साथ ही यहां इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीबीडीटी) का बोर्ड लगा लिया। आरोपित ने साथी सुनील मंडलोई को सीनियर फील्ड ऑफिसर (एसएफओ), रवि सोलंकी को सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (एसआइओ), दुर्गेश गेहलोत को निज सहायक (पीए) और सतीश गावड़ को ड्राइवर और गनमैन बना दिया। आरोपित असली अधिकारियों की तरह अलग-अलग केबिन में बैठकर लैपटॉप और कंप्यूटर पर आयकर संबंधी कार्य करते थे। ठगोरों ने पढ़े-लिखे युवाओं को आयकर विभाग में नौकरी का झांसा दिया और उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। विभिन्न पदों पर पोस्टिंग कर उन्हें नियुक्ति पत्र व आइडी कार्ड बनाकर थमा दिए। एक वर्ष तक उन्हें आयकर विभाग और छापे की कार्रवाई के बारे में पढ़ाया गया। ट्रेनिंग पूरी होने पर उनसे बड़े कारोबारियों, प्रॉपर्टी ब्रोकर, किसान, दुकानदारों का गोपनीय सर्वे करवाया। आरोपितों ने 30 लोगों के ठिकानों पर छापा मारने की तैयार कर ली थी।

# गंगा रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए शासन

**जागरण संवाददाता, हरिद्वार**

मातृसदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने शासन-प्रशासन पर गंगा के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के आदेशों को जिला प्रशासन ने लागू नहीं किया है। खनन रोकने में प्रशासन विफल रहा। ऐसे में गंगा रक्षा के लिए मातृसदन का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, 182 दिन से गंगा रक्षा के लिए तपस्यारत मातृसदन के संत ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि प्रशासन तपस्या को गंभीरता से न लेकर उनके खिलाफ षडयंत्र रच रहा है। अगर गंगा रक्षा आंदोलन के दौरान उन्हें नुकसान होता है तो इसके लिए प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार होंगे।

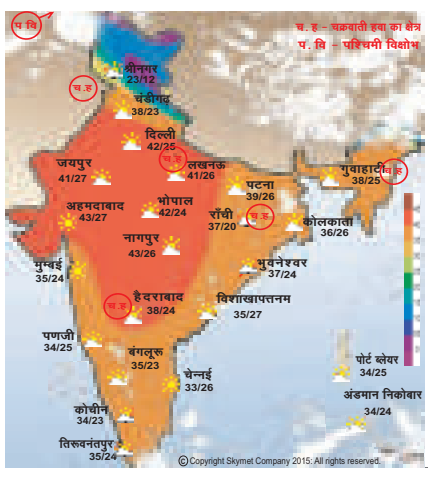


## मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी संभव है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लू की संभावना है। जबकि पंजाब और हरियाणा के एक-दो स्थानों पर गरज व हल्की वर्षा संभव है। दिल्ली का मौसम शुष्क व काफी गर्म बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

| शहर | | शहर | |
|---|---|---|---|
| मुम्बई | 36/25/व | अहमदाबाद | 44/23/आंबा |
| कोलकाता | 37/27/सा | बड़ोदा | 45/26/सा |
| चेन्नई | 34/27/आंबा | नागपुर | 43/27/व |
| हैदराबाद | 39/25/सा | इन्दौर | 44/27/सा |
| बंगलूरू | 36/24/सा | रांची | 46/26/सा |
| त्रिवेन्द्रम | 34/24/आंबा | पटना | 46/29/सा |
| गुवाहाटी | 36/26/आंबा | जमशेदपुर | 43/25/आंबा |
| गंगटोक | 16/05/आंबा | पुणे | 29/24/आंबा |